NRrhlx<+ 'kklu
वित्त विभाग

izsl foKfIr fnukad 13@03@2015

ctV 2015&16

ctV ,d utj esa % ctV vkdkj esa lokf/kd o`f)

(राशि करोड़ में)

en~	jkf'k ¼djksM+ esa½	izfr'kr o`f)
कुल आय	64,935 (54,660)	18
dqy 0;;	65,013 (54,710)	18
सकल वित्तीय घाटा	6,836 (सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत)	कोई वृद्धि नहीं (सीमा के अंदर)

{ks=okj 0;; % iwathxr 0;; esa 39 izfr'kr o`f)

आयोजना व्यय	39,500 (61 प्रतिशत)
पूंजीगत व्यय	11,000 (17 प्रतिशत)

vkfnoklh mi;kstuk {ks= esa 0;;

अनुसूचित जनजाति उपयोजना व्यय	36 प्रतिशत
अनुसूचित जाति उपयोजना व्यय	12 प्रतिशत

fodklewyd 0;;

जी.एस.डी.पी. का	23 प्रतिशत

_.k Hkkj

वर्ष 2015–16 के ऋण की सीमा	6,836
अब तक कुल ऋण भार	30,613
कुल ऋण भार GSDP के प्रतिशत के रूप में	15, न्यूनतम (सभी राज्यों का औसत 24)

ctV dh izkFkfedrk;sa

;qok] v/kkslajpuk fodkl ,oa vkS|ksfxd fodkl

;qFk

- माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक–इन–इंडिया तथा स्किल्ड इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ठोस पहल है। अधोसंरचना के विकास से इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट तथा औद्योगिक विकास को ऊर्जा मिलेगी एवं भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के लिए युवाओं के कौशल उन्नयन का विशेष महत्व है।

- इस बजट के साथ पहली बार ''यूथ बजट'' प्रस्तुत किया जा रहा है। युवाओं के विकास के लिए बजट में कुल 6 हजार 151 करोड़ आवंटित किया गया है, जो कि कुल आयोजना व्यय का 16 प्रतिशत है। युवाओं को कौशल उन्नयन के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अब तक का सर्वाधिक 735 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

- इस साल 17 नये आई.टी.आई. तथा 3 पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे।

- युवा समग्र विकास योजना चालू कर आई.टी.आई., तकनीकी विश्वविद्यालय व व्यापम की प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी और आई.टी.आई. की फीस में भी 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

v/kk lajpuk

- इस बजट में अधोसंरचना के विकास पर सर्वाधिक 11 हजार करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है।

- प्रदेश में रोड नेटवर्क के उन्नयन के लिए 5 हजार 183 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य राजमार्ग तथा सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों को डबल लेन में उन्नयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप मोड से 2 हजार कि.मी. लंबाई की सड़कों का भी उन्नयन किया जाएगा, जिस पर 3 वर्ष में 10 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु 700 करोड़ आबंटित किया गया है।

- लगभग 5 हजार करोड़ के निवेश से 300 कि.मी. के रेल कॉरीडोर का विकास किया जाएगा।

- रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप बनाया जाएगा।

vk|kfxd fodkl

- औद्योगिक विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की गई है।

- नया रायपुर में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए ट्रिपल आई.टी. प्रारम्भ हो जाएगा।

- 17 जिला मुख्यालय में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा।

xjhc] fdlku] etnwjksa ds dY;k.k ds izfr gekjh izfrc)rk tkjh jgsxhA

- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु लगभग 5 हजार करोड़ का प्रावधान है।

- कृषि बजट के लिए 10 हजार 700 करोड़ आबंटित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

- सिंचाई क्षमता के विस्तार हेतु विशेष महत्व दिया गया है एवं इस हेतु 2 हजार 700 करोड़ आबंटित है।

- निराश्रित पेंशन राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, गत वर्ष भी इतनी ही वृद्धि की गई थी। इससे 16 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

- प्रदेश के टीबी. मरीजों को ईलाज के साथ–साथ पूरक पोषण की अभिनव योजना लागू की जाएगी। ऐसा करने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।

- बच्चों में डायबिटीज के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जाएगी।

- शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया में सुलभ शौचालय तथा व्यक्तिगत शौचालय हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है।

efgyk l'kDrhdj.k

- रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में कामकाजी महिलाओं के लिए 15 करोड़ की लागत से महिला हॉस्टल प्रारम्भ किए जाएंगे।

- बालिकाओं में उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विस्तार हेतु 4 हजार सीटों के 80 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

vuqlfpr tkfr@tutkfr

- ट्रायबल सबप्लान के लिए 36 प्रतिशत आयोजना व्यय प्रावधानित है, जबकि जनसंख्या का अनुपात 32 प्रतिशत है।

- अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 11 आई.टी.आई. तथा 1 पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे।

- इन क्षेत्रों में 100 हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन तथा 50 कन्या छात्रावास निर्माण किए जाएंगे।

- आश्रम छात्रवृत्ति 750 से बढ़ाकर 800 रुपए तथा भोजन सहायक राशि 400 से बढ़ाकर 500 रुपए की जाएगी।

dj iLrko

- 1 करोड़ तक वार्षिक बिक्री वाले छोटे एवं मध्यम व्यवसाइयों को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने से मुक्ति ।

- मंदी से राज्य के आयरन–स्टील उद्योगों को राहत देने के लिये रि–रोल्ड उत्पाद पर वैट की दर 5 से घटाकर 4 प्रतिशत ।

- सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को राहत देने के लिये प्रवेश कर से छूट हेतु पूंजी विनियोजन की सीमा रुपये 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ ।

- प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बायो–टायलेट पर प्रचलित 14 प्रतिशत वैट तथा प्रवेश कर समाप्त ।

- अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवास निर्माण में उपयोग हेतु प्री–कास्ट, प्री–फैब्रीकेटेड, मोनोलिथिक कांक्रीट निर्माण पर वैट तथा प्रवेश कर समाप्त।

- एविएशन टरबाईन फ्यूल पर वैट की दर 5 से घटाकर 4 प्रतिशत ।

o"k 2014&15 dh vkfFkd fLFkfr

e[; fcUn

– वर्ष 2014–15 के लिए प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर 13.20 प्रतिशत अनुमानित। इसी अवधि में देश की विकास दर 11.59 प्रतिशत अनुमानित।

– कृषि क्षेत्र में विकास दर 14.18 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 10.62 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 15.21 प्रतिशत की वृद्धि।

– वर्ष 2014–15 के प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) रुपए 2 लाख 10 हजार 192 करोड़ अनुमानित।

– वर्ष 2014–15 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 64,442 रुपए अनुमानित, 2013–14 के लिए 58,547 रुपए की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि।

o"k 2015&16 ctV d e[; vkd"k.k

fdlkuk d fy,

- सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–30 करोड़

- ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण – 158 करोड़ ।

- दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर 1000 रूपए प्रति क्विंटल अनुदान।

- जैविक खेती मिशन –10 करोड़।

- रायपुर में बॉयो कंट्रोल प्रयोगशाला।

- 180 नए कृषि सेवा केन्द्र – 15 करोड़।

- गन्ना कृषकों के लिए पण्डरिया मे नवीन सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना।

- सिंचाई परियोजनाएं – 2,758 करोड़।

- कृषि पंपो को निःशुल्क विद्युत प्रदाय – 1230 करोड़।

- पम्प ऊर्जीकरण – 185 करोड़।

xjhck d: fy,

- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा – 5 हजार करोड़ ।
- पहली बार टी.बी. मरीजों को उपचार के साथ–साथ पोषण प्रदान करने के लिए अक्षय पोषण योजना।
- सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में 50 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि – 700 करोड़।
- असंगठित कर्मकार कल्याण – 40 करोड़।
- मुख्यमंत्री आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग के लिए 50 हजार एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 01 लाख की सब्सिडी –50 करोड़।
- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन – 15 करोड़।
- बीपीएल परिवारों के लिए एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन – 269 करोड़।

ckfydkvk ,o efgykvk d fy,

- नोनी सुरक्षा योजना – 80 करोड़ ।
- सबला कार्यक्रम – 153 करोड़ प्रावधान ।
- महिला कोष से ऋण हेतु – 6 करोड़।
- 06 जिलों में महिला अपराध अनुसंधान की स्थापना।
- आई.टी.आई. एवं पॉलिटेंक्निक छात्राओं के लिए 23 कन्या छात्रावास की स्थापना।

cPpk d fy,

- मधुमेह पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसूलिन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा योजना।

- श्रवण बाधित बच्चों के लिए बालश्रवण योजना।

- जिला स्तर पर नवजात चिकित्सा इकाई तथा विकासखण्ड स्तर पर नवजात देखभाल केन्द्र की स्थापना।

- आंगनबाड़ी केन्द्रों को जीवंत बाल विकास केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

- छः माह से तीन वर्ष उम्र के कुपोषित बच्चों को पका भोजन देने के लिए राज्यपोषित फुलवारी योजना – 30 करोड़।

- आंगनबाड़ी में पूरक पोषण आहार योजना के लिए – 506 करोड़।

- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना – 601 करोड़।

;qokvksa d fy,

- युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए युवा क्षमता विकास योजना।
- कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए – 735 करोड़।
- दुर्ग में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना।
- बस्तर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग तथा राजनांदगांव में आदर्श आवासीय महाविद्यालय की स्थापना।
- 36 महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जायेंगे।
- अंबिकापुर तथा राजनांदगांव चिकित्सा महाविद्यालय – 79 करोड़।
- महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई सुविधा।
- 17 नवीन आई.टी.आई. तथा 03 नवीन पॉलिटेक्निक की स्थापना।
- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में कामकाजी महिला हॉस्टल–15 करोड़।
- लावलीहुड कॉलेजों के भवन एवं छात्रावास निर्माण – 75 करोड़।
- जनवरी, 2016 में राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजन हेतु 12 करोड़।

vu|lfpr tkfr ,o tutkfr ox d fy,

- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में हरियाली प्रसार योजना – 60 करोड़।
- कांकेर में ''प्रयास'' विद्यालय स्थापना।
- ''पोटा केबिन'' आवासीय विद्यालयों में 1,655 सीट वृद्धि।
- 500 आश्रम एवं छात्रावास में शौचालय निर्माण।
- शिष्यवृत्ति, भोजन सहाय की राशि तथा क्रीड़ा परिसर में पोषण आहार राशि में वृद्धि।
- 25 पूर्व माध्यमिक शाला तथा 20 हाईस्कूल का उन्नयन ।
- 15 ग्रामीण समूह नल जल योजना।

v/kkjpuk fuekZ.k

- वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम का गठन किया गया है। इसके माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करने बाबत् वातावरण निर्माण किया जाएगा।

- सड़क निर्माण – 5,183 करोड़।

- पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप पद्धति से टोल रोड तथा एन्युटी आधारित 2000 किलोमीटर सड़को का उन्नयन।

- 19 शहरों में बाईपास निर्माण – 53 करोड़।

- 5 फ्लाईओवर, 11 रेलवे ओव्हरब्रीज तथा अंडरब्रीज निर्माण – 62 करोड़।

- नगर निगम तथा नगरपालिका क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधायुक्त हाईटेक बसस्टैंड का निर्माण।

- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर स्थापना – 26 करोड़।

- धमतरी में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क – 10 करोड़।

xkeh.k {k= v/kkjpuk

- स्वच्छ भारत अभियान – 300 करोड़।
- ''मुख्यमंत्री ग्राम सड़क'' योजना – 700 करोड़ ।
- ''मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ'' योजना – 250 करोड़ ।
- ''मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास'' योजना – 600 करोड़।

lLdfr ,o i;Vu

- सिरपुर का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन के रूप में विकास ।
- बहुआयामी संस्कृति संस्थान निर्माण – 10 करोड़।